सुनकारा लक्ष्मीनारासम्मा (डी) द्वारा कानूनी प्रतिनिधत्व

बनाम

सागी सुब्बा राजू और अन्य वगैरह

(सिविल अपील संख्या 4380-4382/ 2016)

नवंबर 28, 2018

[एन. वी. रमना, मोहन एम. शांतनागौदर और एम. आर. शाह, जे.जे.]

अपील - रखरखाव - जब प्रतिवादियों को या तो पक्षकारों की श्रृंखला से हटा दिया गया था या मृत और जिनके कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया था - अपीलकर्ता-वादीगण ने संपत्तियों के विभाजन के लिए दो मुकदमे दायर किए (अनुसूची ए और बी), जिनमें से एक प्रतिवादी संख्या 26 से 125 और 127 को बेदखली के लिए भी था - अनुसूची ए संपत्ति से संबंधित वसीयत को एक 'एसपी' (वी के दादा के भाई) द्वारा 'वी' के पक्ष में निष्पादित किया गया था-अनुसूची बी संपत्ति से संबंधित एक अन्य वसीयत को उनके पिता (वादी 'एल') द्वारा 'वी' के पक्ष में निष्पादित किया गया था - प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127 जिन्होंने 'वी' से अनुसूची बी संपत्ति खरीदी थी, जिनके लाभ के लिए वसीयत/वसीयत पर भरोसा किया गया था। - संपत्तियों के विभाजन के वाद विचारण न्यायालय द्वारा ख़ारिज किये गए और प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गयी - 'प्रतिवादियो में में से एक 'एस' नमक ने अनुसोछु ए संपत्ति के बेचन के करार की विनिर्दिस्ट अनुपालना के लिए एक वाद दायर किया - विनिर्दिस्ट अनुपालना का वाद अंततः अपीलार्थियो के विरुद्ध डिक्री किया गया - अपीलार्थियो ने तर्क दिया की 'वी' को वाद की संपत्तियो पर पूरी तरह से कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं था और विचारण न्यायालयों का यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं था कि प्रश्नगत संपत्तियो

के सम्बन्ध में प्रतिवादियो द्वारा जिन वसीयतों पर भरोसा किया गया था, वे साबित हो गयी हैं - प्रतिवादियो ने तर्क दिया कि अपीलें सुनवाई योग्य नहीं हैं क्योंकि कई प्रतिवादी जिनके खिलाफ राहत की मांग/ दावा किया गया था, उन्हें या तो पक्षकार श्रंखला से हटा दिया गया था, या मर चुके थे - अपील में, अभिनिर्धारित किया: तीनों न्यायालयों ने तथ्यों पर समवर्ती रूप से यह निष्कर्ष निकाला है कि 'वी' के लाभ के लिए वसीयत साबित की गई थी और दोनों वसीयतों के प्रमाण के संबंध में दिए गए कारण और निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित थे - चूंकि 'वी' वसीयत के आधार पर संपत्तियों का एकमात्र मालिक था, इसलिए उसे संपत्तियों को अलग करने का अधिकार था - प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127 ने मूल्यवान प्रतिफल पर संपत्तियों को 'वी' से खरीदा है - अधीनस्थ न्यायालयों को यह निष्कर्ष निकालने में न्यायसंगत ठहराया गया कि प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127 के पक्ष में की गई बिक्री न्यायसंगत और उचित थी - इस प्रकार, नीचे दिए गए न्यायालयों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था - इसके अलावा, संपत्तियों का विक्रेता 'वी' ने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह घेरे में प्रवेश किया था और प्रतिवादियों के पक्ष में अपने सभी अलगाव का समर्थन किया था - इसलिए, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ सही फैसला किया और विशिष्ट अनुपालना के लिए डिक्री को मंजूरी दी - जहां तक इन अपीलों की स्थिरता का संबंध है, उन प्रतिवादियों के पक्ष में पारित डिक्री जो या तो हटा दिए गए थे या मृत थे और जिनके कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, अन्तिमता को प्राप्त किया था - यदि अन्य प्रतिवादियों के संबंध में इन अपीलों को स्वीकार किया जाता है, तो इन अपीलों में पारित की जाने वाली डिक्री अन्य प्रतिवादियो के पक्ष में पहले ही पारित डिक्री के साथ टकराव होगी - एक ही विषय वास्तु के बारे में दो असंगत डिक्री देने के लिए न्यायालय को नहीं कहा जा सकता - इस प्रकासर, अपीलें चलने योग्य नहीं है - सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 - आदेश XXII, नियम 4.

अपीलों को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया : 1. प्रदर्श बी4, वसीयत अनुसूची ए संपत्ति से संबंधित है। उक्त वसीयत 'एसपी' द्वारा निष्पादित की गई थी, जो निश्चित रूप से अनुसूची ए संपत्तियों का मालिक था। उसे कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु के तुरंत बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उक्त वसीयत के तहत लाभार्थी 'वी' था। प्रदर्श बी106, वसीयत अनुसूची बी संपत्ति से संबंधित है। उक्त वसीयत को 'एल' ('वी' के पिता) द्वारा अपने बेटे 'वी' के पक्ष में निष्पादित किया गया था।'एसपी' और 'एल' के निधन के बाद 'वी' अनुसूची ए और बी संपत्तियों का मालिक बन गया। तीनों न्यायालयों ने तथ्यों पर एक साथ यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों वसीयतें साबित हुई हैं। वसीयतों आदि की वैधता के निष्कर्षों पर अपीलकर्ताओं द्वारा गंभीर रूप से विवाद नहीं किया गया है। अन्यथा भी, तीनों न्यायालयों के निर्णयों को देखने पर, दोनों वसीयतों के प्रमाण के संबंध में दिए गए कारण और निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित हैं। इसलिए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 5] [228-डी, जी-एच]

2. चूंकि 'वी' प्रदर्श बी4 और बी106 वसीयतों के आधार पर संपत्तियों का एकमात्र मालिक था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे संपत्तियों को अलग करने का अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127 ने 'वी' से मूल्यवान प्रतिफल में संपत्तियों को खरीदा था। इन प्रतिवादियों/खरीदारों के पक्ष में किए गए अलगाव पर विभाजन के लिए दो वादों में अपीलकर्ताओं द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था। जो भी हो, चूंकि प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127 के पक्ष में की गई बिक्री न्यायसंगत और उचित है और चूंकि वे मूल्यवान प्रतिफल के अधर पर प्रामाणिक खरीदार हैं, इसलिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। [पैरा 6] [229-ए-बी]

3. चूँकि 'वी' विशिष्ट अनुपालना के लिए वाद में शामिल संपत्ति सहित संपत्तियों का पूर्ण मालिक था, इसलिए उसे बिक्री का समझौता करने का भी अधिकार था। यह संपत्ति 'एसपी' द्वारा प्रदर्श बी4 वसीयत के तहत 'वी' को विरासत में दी गई थी। इसलिए, 'वी' संपत्ति का एकमात्र मालिक था। नतीजतन, उसने 'एस' के साथ बिक्री का समझौता किया था। वास्तव में, संपत्तियों के विक्रेता 'वी' ने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह बॉक्स में प्रवेश किया था और प्रतिवादियों के पक्ष में अपने सभी अलगाव का समर्थन किया था। इसलिए, खंड पीठ ने 'एस' के पक्ष में और अपीलार्थियों के खिलाफ सही निष्कर्ष निकाला है और विशिष्ट अनुपालना के लिए डिक्री को मंजूरी दी है। [पैरा 7] [229-डी-ई; 230-बी]

4. आदेश 22 नियम 4, सी. पी. सी. में कहा गया है कि जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर, मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहां मृत प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमा समाप्त हो जाएगा। इस नियम में यह प्रावधान नहीं है कि प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को शामिल करने में चूक से, मुकदमा समग्र रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि सह-प्रतिवादियों के हित अलग हैं, जैसा कि सह-मालिकों के मामले में है, तो वाद केवल मृतक पक्ष के विशेष हित के संबंध में समाप्त होगा। ऐसी स्थिति में, इस मामले में उत्पन्न हुई अपील को पूरी तरह से कम करने का सवाल सामान्य सिद्धांतों पर निर्भर करता है। यदि मामला ऐसी प्रकृति का है कि मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति न्यायालय को अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अपील की सुनवाई करने से रोकती है, तो अपील पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अन्यथा, उपशमन केवल उस प्रत्यर्थी के हित के संबंध में होता है जिसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे मामलों में अक्सर यह परीक्षण अपनाया जाता है कि शेष प्रतिवादियो के खिलाफ अपील की अनुमति दिए जाने की स्थिति में एक ही विषय वस्तु के संबंध में

एक ही मुकदमे में दो विरोधाभासी फरमान होंगे या नहीं। न्यायालय को एक ही संपत्ति के बारे में दो असंगत डिक्री के लिए नहीं कहा जा सकता है, और परस्पर विरोधी डिक्री से बचने के लिए न्यायालय के पास समग्र रूप से अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि दूसरी ओर, अपील की सफलता से परस्पर विरोधी आदेश नहीं मिलते हैं, तो कोई वैध कारण नहीं है कि न्यायालय को अपील पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए और पक्षों के बीच विवाद पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हस्तगत मामले में, कुछ प्रतिवादियों की अनुपस्थिति जिन्हें पक्षों की श्रृंखला से हटा दिया गया है और साथ ही कई मृत प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति न्यायालय को अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने से रोकेगी। क्योंकि शेष प्रतिवादियों के विरुद्ध इन अपीलों की अनुमति दिए जाने की स्थिति में, एक ही विषय वस्तु के संबंध में एक ही वाद में दो विरोधाभासी डिक्री होंगी। एक डिक्री बचाव पक्ष के पक्ष में होगी जो हटा दिए गए हैं या मृत हैं और जिनके कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है; जबकि दूसरा डिक्री उन प्रतिवादियों के खिलाफ होगी जो अभी भी उसी विषय के संबंध में अभिलेख पर हैं। न्यायालय को एक ही विषय के बारे में दो असंगत आदेश देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। परस्पर विरोधी डिक्री से बचने के लिए, न्यायालय के पास अपीलों को पूरी तरह से खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। [पैरा 9] [230-एफ-एच; 232-ए-जी]

शहज़ादा बी बनाम हलीमाबी, (2004) 7 एस. सी. सी. 354:[2004]

3 पूरक एस.सी.आर 222 - पर निर्भरता

<u>निर्णय विधि संदर्भ</u>

[2004] 3 पूरक एस.सी.आर. 222 निर्भरता पैरा 7

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारिता : सिविल अपील सं. 4380-4382/ 2016

पत्र पेटेंट अपील सं. 323/ 1992 और 2001 की अपील सं. 2959 और 2960 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद के दिनांक 11.09.2003 के निर्णय और आदेश से।

ए. सुब्बा राव, के.एल.डी.एस. विनोबर, अधिवक्तागण, अपीलार्थियों के लिए।

थॉमस पी. जोसेफ, वरिष्ठ अधिवक्ता, वी. एन. रघुपति, आर. वी. कामेश्वरन, मुल्लापुडी रामबाबू, अजय चौधरी, वी. श्रीधर रेड्डी, अभिजीत सेनगुप्ता, अधिवक्तागण, प्रतिवादियो के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

मोहन एम. शांतनागौदर, न्यायाधिपति

1. ये अपीलें लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 323/ 1992 और 2001 की अपील संख्या 2959 और 2960 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद द्वारा पारित सामान्य निर्णय दिनांक 11 सितम्बर 2003 के खिलाफ निर्देशित की गई हैं। इसमें अपीलकर्ता अधीनस्थ न्यायाधीश, भीमावरम (पूर्व में ओ. पी. No.124/1980) की फाइल पर ओ. एस. संख्या 98/ 1984 और अधीनस्थ न्यायाधीश, भीमावरम (पूर्व में ओ. पी. No.10/1982) की फाइल पर ओ. एस. संख्या 97/ 1984 में वादी थे। वे अधीनस्थ न्यायाधीश, भीमावरम (पूर्व में अधीनस्थ न्यायाधीश, नरसापुर की फाइल पर ओ. एस. संख्या 72/1983 (पूर्व में ओ. पी. No.32/1978) में प्रतिवादी थे।

2. ओ. एस. सं. 98/ 1984 प्रतिवादी सं. 5 से 25 के विरुद्ध अनुसूची ए संपत्ति के विभाजन के लिए दायर किया गया था। इस वाद में, वीरास्वामी (वादी लक्ष्मीनारासम्मा के बेटे) द्वारा किए गए केवल एक अलगाव को चुनोती दी थी, हालांकि वीरास्वामी ने अनुसूची ए के तहत आने वाले विभिन्न बिक्री विलेखों के

माध्यम से कई अन्य संपत्तियों को अलग कर दिया था। ओ.एस. संख्या 97/1984 अनुसूची ए और बी संपत्तियों के विभाजन के साथ-साथ प्रतिवादी संख्या 26 से 125 और 127 को उक्त संपत्तियों से बेदखली के लिए दायर किया गया था। ओ.एस. संख्या 72/ 1983 एक सागी सुब्बा राजू (इन अपीलों में प्रतिवादियो में से एक) द्वारा द्निंक 19.07.1974 के बिक्री समझोता, जो स्वर्गीय वीरस्वामी द्वारा ग्राम भीमावरम के राजस्व सर्वेक्षण संख्या 347 और 347/3 में 3 एकड़ 56 सेंट की सीमा को सम्मिलित करते हुए निष्पादित किया गया, के विशिष्ठ अनुपालना के लिए दायर किया गया था।

ओ.एस. संख्या 97/1984 और 98/ 1984 (अनुसूची ए और बी संपत्तियों के विभाजन के लिए) को विचारण न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी। ओ. एस. संख्या 72/ 1983 (विशिष्ट अनुपालना के लिए दावा) को आंशिक रूप से डिक्री किया गया था, जिसमें वादी सागी सुब्बा राजू के पक्ष में संपत्ति के एक तिहाई हिस्से की बिक्री का निर्देश दिया गया था, और इस तरह के आदेश की पुष्टि पहले अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई थी। इन निर्णयों और डिक्रीओं से व्यथित महसूस होते हुए, असफल अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। इसी तरह, सागी सुब्बा राजू, जिसे विशिष्ट अनुपालना के लिए दावे में संपत्ति का एक तिहाई हिस्सा मिलना था, ने उच्च न्यायालय के समक्ष एल.पी.ए. संख्या 323/ 1992 दायर किया। इन सभी अपीलों की सुनवाई उच्च न्यायालय द्वारा एक साथ की गई थी और इसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ निर्णय लिया गया था, जिसका अर्थ है कि ओ. एस. संख्या 97 और 98/ 1984 में पारित किए गए निर्णयों और ख़ारिज की गयी डिक्रीओं की पुष्टि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा भी की गई थी।अतः अपीलार्थियों द्वारा इसमें अपीलार्थियों के विरुद्ध विभाजन के लिए दायर किए गए उन दो दावों के

संबंध में तीन न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। ओ. एस. संख्या 72/ 1983 के संबंध में भी, खंड पीठ ने सागी सुब्बा राजू के पक्ष में और इसमें अपीलकर्ताओं के खिलाफ एक डिक्री देने के लिए आगे बढ़े, जैसा कि अनुरोध किया गया था। दूसरे शब्दों में, विशिष्ट अनुपालना के लिए दावा भी इसमें अपीलार्थियों के खिलाफ पूरी तरह से तय किया गया था। इसलिए, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष हैं।

3. श्री ए. सुब्बा राव, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, हमें अभिलेख पर सामग्री के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कि नीचे दिए गए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में उचित नहीं थे कि प्रतिवादियों द्वारा वसीयत (वसीयत) पर भरोसा किया गया था, यानी अनुसूची ए संपत्ति और वसीयत दिनांक 05.10.1968 (प्रदर्श B106/प्रदर्श पी2) वीरास्वामी के लाभ के लिए निष्पादित अनुसूची बी संपत्ति के संबंध में साबित किया गया था; कि वादी को वाद संपत्ति में दो तिहाई हिस्सा मिला है और इसलिए वसीयत (प्रदर्श बी4 और बी106) लाभार्थी को शेष एक तिहाई संपत्ति से अधिक का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127, वीरास्वामी (जिनके पक्ष में वसीयतों को निष्पादित किया गया था) से संपत्तियों के खरीदार होने के नाते, बेदखल किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि वीरास्वामी का दावे की संपत्तियों पर पूरी तरह से कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं था, दूसरी ओर, वीरास्वामी का मुकदमे की संपत्तियों में केवल एक तिहाई हिस्सा था।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादिओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का निर्णय न्यायसंगत और उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने माना है कि प्रदर्श बी4 और प्रदर्श बी106 कानून के अनुसार साबित हुए हैं और परिणामस्वरूप वीरास्वामी उक्त

वसीयतों से संपत्ति के मालिक बन गए। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी/खरीदार 40 से 50 से अधिक वर्षों से दावे की संपत्तियों के शांतिपूर्ण कब्जे में हैं और कुछ प्रतिवादियों ने संपत्तियों को तीसरे पक्ष को भी हस्तांतरित कर दिया है। अंत में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अपीलें विचारणीय नहीं हैं क्योंकि इसमें अपीलकर्ताओं द्वारा कई प्रतिवादियों (वीरास्वामी के खरीदारों) को पक्षकारों की श्रृंखला से हटा दिया गया था, और कुछ प्रतिवादियों की मृत्यु दावों के साथ-साथ पहली अपील और दूसरी अपील के लंबित रहने के दौरान हुई है और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को अपीलकर्ताओं द्वारा यहाँ अभिलेख पर नहीं लाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष भी कुछ प्रतिवादियों/प्रत्यर्थियों की अवधि समाप्त हो चुकी है।याचिकाकर्ताओं ने ऐसे मृत प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने की जहमत नहीं उठाई। परिणामस्वरूप, मृतक और हटाए गए प्रतिवादियों के पक्ष में पारित डिक्री ने यह मानते हुए कि वीरास्वामी को संपत्ति बेचने का अधिकार था, अंतिमता प्राप्त कर ली है, और परिणामस्वरूप ऐसे प्रतिवादियों के पक्ष में की गई बिक्री भी अंतिमता प्राप्त कर चुकी है। दूसरे शब्दों में, मृतक/हटाए गए प्रतिवादियों के संबंध में वसीयतों के साथ-साथ बिक्री विलेखों की वैधता की पुष्टि होती है और इसलिए ये अपीलें, जो इस न्यायालय के समक्ष अन्य प्रतिवादियों के संबंध में विचाराधीन हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए खारिज की जा सकती हैं कि यदि कोई आदेश यहां प्रतिवादियों/शेष प्रतिवादियों के हित के प्रतिकूल पारित किया जाता है, तो यह उन निर्णयों और डिक्रीओं के साथ विरोधाभासी होगा जिनकी पहले से ही मृतक/हटाए गए प्रतिवादियों के खिलाफ पुष्टि की जा चुकी है।

5. प्रदर्श बी4, वसीयत दिनांक 14.08.1932, अनुसूची ए संपत्ति से संबंधित है। उक्त वसीयत को सुनकारा पद्मनाभुडु द्वारा निष्पादित किया गया था, जो निश्चित रूप से अनुसूची ए संपत्तियों के मालिक थे। उसके कोई संतान नहीं थी। उनकी मृत्यु

के तुरंत बाद उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो गई। उक्त वसीयत के तहत लाभार्थी वीरास्वामी थे, जो कोई और नहीं बल्कि सुनकारा वेंकटरमैया (सुनकारा पद्मनाभुडु के भाई) के पोते हैं। प्रदर्श बी106, अनुसूची बी संपत्ति से संबंधित वसीयत दिनांकित 05.10.1968 है। उक्त वसीयत को लक्ष्मीपति (वीरास्वामी के पिता) ने अपने बेटे वीरास्वामी के पक्ष में निष्पादित किया था। सुनकारा पद्मनाभुडु की मृत्यु 20.08.1932 को हुई और लक्ष्मीपति की मृत्यु 21.01.1969 को हुई। इस प्रकार, सुनकारा पद्मनाभुडु और लक्ष्मीपति के निधन के बाद, वीरास्वामी अनुसूची ए और बी संपत्तियों के मालिक बन गए। अभिलेख पर यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि अनुसूची बी में संपत्तियां लक्ष्मीपति और उनके बेटे की संयुक्त संपत्तियां थीं। इसलिए भी, वादी द्वारा यह स्थापित नहीं किया गया है कि अनुसूची बी की संपत्तियां विभाजन के लिए उपलब्ध थीं। विभाजन के दावों में अपीलार्थियों/वादियों के खिलाफ उक्त बिंदु पर तीन न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं। वादी लक्ष्मीनारासम्मा लक्ष्मीपति की दूसरी पत्नी है, जिसने ओ. एस. संख्या 97 और 98 ऑफ़ 1984 दाखिल करके प्रतिवादी संख्या 5 से 125 के पक्ष में अपने बेटे वीरास्वामी द्वारा किए गए अलगाव पर विशेष रूप से सवाल नहीं उठाया है। बिक्री विलेख को रद्द कराने के लिए उनकी कोई प्रार्थना नहीं है। तीनों न्यायालयों ने तथ्यों पर एक साथ यह निष्कर्ष निकाला है कि दोनों वसीयतें साबित हुई हैं। हमसे पहले भी, वसीयतों आदि की वैधता के निष्कर्षों पर अपीलकर्ताओं द्वारा गंभीर रूप से विवाद नहीं किया गया है। अन्यथा भी, तीनों न्यायालयों के निर्णयों को देखने पर, हम पाते हैं कि दोनों वसीयतों के प्रमाण के संबंध में दिए गए कारण और निष्कर्ष न्यायसंगत और उचित हैं। इसलिए, किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. चूंकि वीरास्वामी प्रदर्श बी4 और बी106 वसीयतों के आधार पर संपत्तियों के एकमात्र मालिक थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें संपत्तियों को अलग करने का

अधिकार था। प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127 ने वीरास्वामी से मूल्यवान प्रतिफल पर संपत्तियां खरीदी थीं। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन प्रतिवादियों/खरीदारों के पक्ष में किए गए अलगाव पर अपीलकर्ताओं द्वारा विभाजन के लिए उपरोक्त दो दावों में सवाल नहीं उठाया गया था। जो भी हो, क्योंकि हम पाते हैं कि नीचे दिए गए न्यायालय यह निष्कर्ष निकालने में सही हैं कि प्रतिवादी संख्या 5 से 125 और 127 के पक्ष में की गई बिक्री न्यायसंगत और उचित है और चूंकि वे मूल्यवान प्रतिफल पर प्रामाणिक खरीदार हैं, इसलिए किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. जहाँ तक विशिष्ट अनुपालना के लिए दावों का संबंध है, अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री ए. सुब्बा राव हालांकि अपनी दलीलों में प्रबल थे। उनके अनुसार, इसमें अपीलकर्ताओं (विशिष्ट निष्पादन के लिए मुकदमे में प्रतिवादियों) को कठिनाई होगी यदि विशिष्ट अनुपालना के लिए डिक्री की पुष्टि की जाती है, क्योंकि बिक्री के समझौते के बाद से संपत्तियों की कीमत में भारी वृद्धि हुई है। मूल्य में वृद्धि की ऐसी याचिका को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि पहली बार में अपीलकर्ताओं को बिक्री के समझौते पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, चूंकि वीरास्वामी विशिष्ट अनुपालना के लिए दावों में शामिल संपत्ति सहित संपत्तियों के पूर्ण मालिक थे, इसलिए उन्हें बिक्री का समझौता करने का भी अधिकार था। यह संपत्ति पद्मनाभुडु द्वारा प्रदर्श बी4 वसीयत के तहत वीरास्वामी को विरासत में दी गई थी। इसलिए, वीरास्वामी संपत्ति के एकमात्र मालिक थे। नतीजतन, उन्होंने 19.09.1974 पर सागी सुब्बा राजू के साथ बिक्री का समझौता किया था। यह दावा वर्ष 1978 में दायर किया गया था, जिसे बाद में दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और इसे ओ. एस. संख्या 72/ 1983 के रूप में फिर से क्रमांकित किया गया था। 1978

से, यह मुकदमा संभावित विक्रेता द्वारा लड़ा जा रहा है। लगभग साढ़े तीन एकड़ की संपत्ति को वीरास्वामी द्वारा वर्ष 1974 में संभावित विक्रेता के पक्ष में रुपये 51,000/- की राशि में बेचने पर सहमति व्यक्त की गई थी। इस तरह की कीमत पर विक्रेता के साथ-साथ संभावित विक्रेता के बीच सहमति बनी थी। यह न्यायालय संपत्ति के मूल्य की कल्पना नहीं कर सकता है जैसा कि वर्ष 1974 में उक्त क्षेत्र में, यानी आंध्र प्रदेश के भीमावरम गांव में था। जो भी हो, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा न तो कठिनाई का अनुरोध किया गया था और न ही साबित किया गया था। विचारण न्यायालय के समक्ष कठिनाई से संबंधित कोई मुद्दा नहीं उठाया गया था। एक याचिका जिसका आग्रह विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया था, उसे पहली बार अपीलीय न्यायालयों के समक्ष उठाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा, केवल मूल्य में वृद्धि इस मामले में इस स्तर पर हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है (नरिंदरजीत सिंह बनाम बनाम नॉर्थ स्टार एस्टेट प्रमोटर्स लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 712 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय देखें) । इसमें जोड़ा गया, इसके लिए, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियों को खंड पीठ के फैसले पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है क्योंकि वे संपत्ति के मालिक नहीं हैं। वास्तव में, संपत्तियों के विक्रेता वीरास्वामी ने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह बॉक्स में प्रवेश किया था और प्रतिवादियों के पक्ष में अपने सभी अलगाव का समर्थन किया था। इसलिए, हमारी सुविचारित राय में, खंड पीठ ने सागी सुब्बा राजू के पक्ष में और अपीलार्थियों के खिलाफ सही निष्कर्ष निकाला है और विशिष्ट अनुपालना के लिए डिक्री को मंजूरी दी है।

8. किसी भी स्थिति में, प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री थॉमस पी. जोसेफ का यह तर्क देना उचित है कि ये अपीलें रखने योग्य नहीं हैं क्योंकि कई प्रतिवादी जिनके खिलाफ राहत मांगी गई है/दावा किया

गया है, या तो पक्षकारों की श्रृंखला से हटा दिए गए हैं, या मर चुके हैं। ऐसे मृत प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है। यहाँ तक की इस न्यायालय के समक्ष, सिविल अपील सं. 4382/2016 @SLP (C) संख्या 20376/2004 में प्रत्यर्थी सं. 7 (D8), प्रत्यर्थी सं. 8 (D9), प्रत्यर्थी सं. 9 (D10) और प्रत्यर्थी No.11 (D13) की मृत्यु हो चुकी है। उनके कानूनी प्रतिनिधियों को भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि प्रतिवादी संख्या 4, 6, 36, 50, 54, 58, 67, 69, 73, 77, 82, 92, 93, 113, 120 और 127 ओ. एस. संख्या 97/ 1984 में विचारण न्यायालय के समक्ष मामले के लंबित रहने के दौरान मर गए थे। इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 20, 53, 64 और 118 की भी मृत्यु हो गई है और उनके कानूनी प्रतिनिधियों को भी अभिलेख पर नहीं लाया गया है।

9. आदेश 22 नियम 4, सी. पी. सी. में कहा गया है कि जहां कानून द्वारा सीमित समय के भीतर, मृत प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है, वहां मृत प्रतिवादी के खिलाफ दावा समाप्त हो जाएगा। इस नियम में यह प्रावधान नहीं है कि प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधि को शामिल करने में चूक से, दावा समग्र रूप से समाप्त हो जाएगा। यदि सह-प्रतिवादियों के हित अलग हैं, जैसा कि सह-मालिकों के मामले में है, तो दावा केवल मृतक पक्ष के विशेष हित के संबंध में समाप्त होगा। ऐसी स्थिति में, इस मामले में उत्पन्न हुई अपील को पूरी तरह से कम करने का सवाल सामान्य सिद्धांतों पर निर्भर करता है। यदि मामला ऐसी प्रकृति का है कि मृतक प्रतिवादी के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति न्यायालय को अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अपील की सुनवाई करने से रोकती है, तो अपील पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अन्यथा, उपशमन केवल उस प्रत्यर्थी के हित के संबंध में होता है जिसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे मामलों में अक्सर यह परीक्षण अपनाया जाता है की क्या शेष उत्तरदाताओं के खिलाफ अपील की

अनुमति दी जाने की स्थिति में एक ही विषय वस्तु के संबंध में एक ही मुकदमे में दो विरोधाभासी डिक्री होंगी या नहीं। न्यायालय को एक ही संपत्ति के बारे में दो असंगत डिक्री जरी करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, और परस्पर विरोधी डिक्रीओं से बचने के लिए न्यायालय के पास समग्र रूप से अपील को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यदि दूसरी ओर, अपील की सफलता से परस्पर विरोधी आदेश नहीं मिलते हैं, तो कोई वैध कारण नहीं है कि न्यायालय को अपील पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए और पक्षों के बीच विवाद पर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हस्तगत मामले में, कुछ प्रतिवादियों की अनुपस्थिति जिन्हें पक्षों की श्रृंखला से हटा दिया गया है और साथ ही कई मृत प्रतिवादियों के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति न्यायालय को अन्य प्रतिवादियों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करने से रोकेगी। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि शेष प्रतिवादियों के खिलाफ इन अपीलों की अनुमति दिए जाने की स्थिति में, एक ही विषय वस्तु के संबंध में एक ही मुकदमे में दो विरोधाभासी डिक्री होंगी। एक डिक्री उन प्रतिवादियों के पक्ष में होगी जिन्हें हटा दिया गया है या मृत कर दिया गया है और जिनके कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है; जबकि दूसरा डिक्री उन प्रतिवादियों के खिलाफ होगी जो अभी भी उसी विषय के संबंध में अभिलेख पर हैं। दावे में विषय वस्तु दो वसीयतों की वैधता है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ सहित न्यायालयों ने लगातार यह अभिनिर्धारित किया है कि दोनों वसीयतें साबित हो गई हैं, और इस प्रकार दो वसीयतों के तहत लाभार्थी होने के नाते वीरास्वामी विचाराधीन वाद संपत्तियों के पूर्ण मालिक बन गए थे। इस तरह की डिक्री ने उन प्रतिवादियों के पक्ष में अंतिमता प्राप्त कर ली है जो या तो हटा दिए गए हैं या मर चुके हैं और जिनके कानूनी प्रतिनिधियों को अभिलेख पर नहीं लाया गया है। यदि अन्य प्रतिवादियों के संबंध में इन अपीलों की अनुमति दी जाती है, तो इन अपीलों में इस न्यायालय द्वारा पारित की जाने

वाली डिक्री निश्चित रूप से अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में पहले से पारित डिक्री के साथ संघर्ष करेगी। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, न्यायालय को एक ही विषय के बारे में दो असंगत डिक्री जरी करने लिए नहीं कहा जा सकता है। परस्पर विरोधी डिक्रीओं से बचने के लिए, न्यायालय के पास अपीलों को पूरी तरह से खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है (इस न्यायालय के निर्णय को शहजादा बी बनाम हलीमाबी, (2004) 7 एस सी सी 354 के मामले में में देखें)

10. उपरोक्त के अनुसार, अपील न केवल गैर-रखरखाव के आधार पर, बल्कि गुण-दोष के आधार पर भी विफल हो जाती हैं, और खारिज कर दी जाती हैं।

अंकित ज्ञान

याचिकाएं खारिज की गईं।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।